(8) परिष्कृत किए गए कोयले की मुख्यतः कोयला क्षेत्रों को 1000 किलो मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित दूरस्थ स्थित कुछ विद्युत गृहों के लिए कोयला परिष्कृत किए जाने के लिए स्थापना किया जाना।

कोल इंडिया लिमिटेड के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार हेतु विश्व बैंक से ऋण

5834. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार हेतु विश्व बैंक से एक बिलियन डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ऋण किन-किन निबंधन और शर्तों पर लिया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) और विश्व बैंक के बीच 31 परियोजनाओं के लिए एक सम्भावित ऋण प्राप्त करने हेतु विचार-विमर्श चल रहा है, जिसमें नयी/विस्तार परियोजनायें और विपणन खानों एवं परियोजनाओं में हैवी अर्थ-मूविंग मशीनरी की प्रतिस्थापना का कार्य शामिल है। को०ई०लि० द्वारा विश्व बैंक से लगभग 2932 करोड़ रु० की राशि की सहायता मांगी गई है।

ऋण की शर्तों के संबंध में जानकारी विश्व के साथ चल रहे विचार-विमर्श के निष्कर्ष पर पहुचाने के बाद ही पता चल सकेगा।

Decline in Marine Shrimp Exports

5835. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any analysis has been made of the causes for the decline in exports of marine shrimp;

(b) if so, the details of the study;

(c) whether it is a fact that MPEDA has given less attention to exports of shrimp from oceanic resources; and

(d) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir. There is no decline in the exports of marine shrimp, though landings from capture sources have been stagnating.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Mechanism for fixing input-output norms for Export Products

5836. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the mechanism of fixation of input-output norms for different export products under the Duty Exemption scheme of the Export-Import Policy;

(b) whether there is any system of pre or post export audit for verification of the authenticity of such laid down input-output norms; if so, what are its operational modalities; and

(c) if not, in what manner the correctness of the input-output norms for a large number and varieties of export products is ensured?